the workers regularly. For the last three or four months no payment has been made, for which an enquiry committee has been set up by the State Government. So, will it not be desirable to takee over the factory immediately without any further delay?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI MOHAN KUMARAMANGLAM) : As my colleague, the Minister of State, has already mentioned, a committee has been appointed consisting of Mr. Appu Rao, Director, Hindustan Steel Limited, a repressentative of Bokaro Steel Limited, and the Senior Industrial Adviser in the ministry, Mr. Hari Bushan. We expect their report within this month itself. All the matters raised by the hon. members including my hon. friend there will be taken into consideration before coming to a final decision in the matter.

Industrial Peace in Public Undertakings

*248. SHRI N. K. SINHA : Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state the steps taken to ensure an era of Industrial peace in the country with special reference to the working of public undertakings ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABQUR AND REHABILITATION (SHRI BAL GOVIND VERMA) : The Settlement machinery envisaged under the Industrial Disputes Act, 1947, together with voluntary arrangements like the Code of Discipline, govern industrial relations in the public as well as private sector undertakings. The main effort is to minimise industrial disputes throgh the processes of preliminary discussions, informal mediation, conciliation and adjudication or arbitration, as necessary, under the existing statutory ond voluntary arrangements; Government have also been holding discussions with the workers and employers' representatives with a view to evolving agreed measures for securing needed improvements in the industrial relations system.

SHRI N. K. SINHA : In view of the fact that 1970 was the worst year from this point of view, do Government propose to bring about some kind of structural changes in the organisation of trade unions and also in the management style and also provide for a permanent machinery to settle disputes and introduce some kind of educational and cultural revolution in the factories ?

SHRI BALGOVIND VERMA : So far as changes in the structure of the unions as well as the management of factories are concerned, discussions are being held with the representatives of employees and employers and we have not come to any concrete conclusion. Government are of the opinion that there must be some sort of a change in the structure of the management and workers must be made to feel that they are members of the management and they should share the responsibility of the management as well. But nothing has come out so far. It is under discussion. Regarding permanent machinery, the National Labour Commission is of the opinion that the system which has been in vogue is not of a very satisfactory nature. Therefore, a conference was held of emploees and employers on 20, 21 and 22nd last month respectively. Some consensus has been reached on broad issues but no concrete proposals have come forward. Government have asked the employees to consult among themselves and put forward certain suggesions which may be considered by the Government.

SHRI N. K. SINHA : What are the terms of the agreement so far reached ? Secondly, some kind of cultural and educational revolution on patristic lines has to be brought about in side the factory. What has the Government to say about that ?

SHRI BALGOVIND VERMA : Government have a scheme for workers' education. Workers fare collected from every undertaking and they are put under training. Then these worker go and take classes inside the undertaking. This process is going on. But we are not getting is

much co-operation from the management side as we want. We are looking into it and we will see what we can do in the matter.

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उद्योगों में ये जितने विवाद होते हैं उसके विभिन्न कारण होंगे लेकिन उन कारणों में मुख्य कारण यूनियन्स को मान्यता देने के प्रश्न को लेकर है, तो क्या आप मान्यता उसी यूनियन को देने के प्रश्न पर विचार कर रहे है जो चुनाव के आधार पर मान्यता प्राप्त करे, चुनाव में जिसे बहुमत प्राप्त हो, उसी को आप मान्यता प्रदान करें, ऐसा आप करने जा रहे हैं ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : इस बारे मे भिन्न-भिन्न रायें है। अभी 20 और 21 को एम्प्लाईज के यूनियन्स के रेप्रेजेन्टेटिव्ज की मीटिंग हुई थी और वहा पर दो मत प्रकट किए गए थे। एक तो यह था कि चुनाव करके मेजारिटी तय की जाय कि बहुमत किसका है और दूसरा यह था कि वेरिफिकेशन किया जाय। वेरिफिकेशन के बाद अगर यह मालूम हो कि किसका बहुमत हैं तो उसको मान्यता दी जाय। चूंकि कोई फैसला नही हो पाया था इसलिए गवनमेंट ने जो यूनियन्स के लीडर्स थे उनसे यह कहा कि आप तीन महीने के अन्दर आपस में तय करके एक फैसला दीजिए जिससे कि हम उस पर कार्यवाही कर सकें।

SHRI RAJA KULKARNI : Does the hon. Minister agree that the man-days lost is not the criterion for maintaining industrial peace or settlement of industrial disputes?

SHRI BAL GOVIND VERMA : So far as the man-days lost is concerned, there can be many factors responsible for it. We cannot blame the industrial disputes for the entire man-days lost.

श्री राजाराम बिलकल : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि श्रमिक नेताओं के साथ जो दिल्ली में बातचीत हुई उस में मुख्य मुख्य बातें क्या थी ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो यहाँ श्रमिक नेताओं से बातचीत हुई उसमें मुख्य बात एक तो मान्यता की थी कि मान्यता किस प्रकार दी जाय और एक यह थी कि बारगेनिंग एजेन्ट किस प्रकार से चुना जाय। जहां तक बारगेनिंग एजेन्ट की बात है सभी लोग सहमत हैं कि कम्पोजिट बारगेनिंग एजेन्ट होना चाहिए। जो मान्यता प्राप्त यूनियन्स है जिनके पास मेजारिटी है वह माइनारिटी यूनियन्स के साथ में लेकर के एक अपनी कमेटी बनाए जो कि वहाँ मनेजमेंट से बारगेनिंग करें। इस बात पर सभी की सहमति हो गई है। एक मुख्य बात तो यही है। दूसरी बात जो मान्यता की है वह अभी तक तय नही हो पाई है लेकिन उम्मीद है वह भी तय हो जायेगी।

श्री सरजू पांडेय : अभी रेलवे मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने तमाम रेलवे अधिकारियों को यह आदेश दिया था कि वह उन्हीं यूनियन्स के लोगों से बात करे जो मान्यता प्राप्त हों और बहुत सारी ऐसी यूनियन्स हैं जो फर्जी है जिनका कोई मेम्बरशिप नहीं है और जाली तौर पर उन को मान्यता दी गई है। यहाँ तक कि लोक सभा के सदस्यों का भी कोई रेप्रेजेन्टेशन रेलवे अधिकारी सुनने को तैयार नही है। तो क्या इस सबंध में आप रेलवे मंत्रालय से बात करेंगे कि कम से कम लोक सभा के सदस्य जिन कंसेज को रेप्रेजेन्ट करते है तो उन को तो सुना करें ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जहां तक लोक सभा के सदस्यो की बात है, जो भी बात वे हमारे सामने लाते हैं उस के प्रति केवल लेबर मिनिस्टरी ही नही, बल्कि सभी मिनिस्ट्रिया काफी ध्यान देती है।

जहाँ तक यूनियनो की मान्यता का प्रश्न है—मान्यता प्राप्त यूनियनो को पहले से ही यह सुविधा प्राप्त है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी यूनियनो से भी फैक्टरी या अन्डरटेकिंग बन्द हो जाती है। मान लीजिए एक फैक्टरी मे क्रेन चल रही है, उस मे पचास, साठ आदमी काम करते हैं, उनकी जो यूनियन बनी हुई है यदि वह काआपरेट न करे तो सारी फैक्टरी बन्द हो जाती है। इसलिए यह तय किया गया है कि आगे चल कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि फैक्टरी की प्रोडक्शन बढ सके, उस की प्रोडक्टिविटी न गिरे, इस दृष्टि से यूनियनो के लीडर कोई ऐसा फार्मूला इवोल्व करे कि फैक्टरी मे स्ट्राइक न हो और देश की प्रगति हो सके।

श्री सतपाल कपूर : अध्यक्ष महोदय, बेसिक प्राब्लम यह है कि पब्लिक अन्डर-टेकिंग और प्राइवेट सेक्टर दोनो के साथ ट्रेड यूनिननों के जो एग्रीमेंट हो जाते है, उन पर इम्पलीमेंटेशन नही होता। इस प्रब्लम को दूर करने के लिए मिनिस्ट्री क्या कर रही है?

श्री बालगोविन्द वर्मा : अगर आप कोई स्पेसीफिक मामला हमारे सामने लाएगे तो हम उसको जरूर देखेंगे। वैसे हम यह कोशिश करते हैं कि जिस मामले पर सह-मति हो जाती है या जो बात आपस मे तय हो जाती है उस को जरूर केरी आउट किया जाए।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो मीटिंग हुई थी उस मे अधिकांश यूनियनो के प्रतिनिधियो ने कहा था कि मान्यता के लिए निर्णय चुनाव के माध्यम से होना चाहिये यानि यूनियन को मान्यता चुनाव के आधार पर दी जानी चाहिए।

श्री बालगोविन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होने सजेशन दी है। अभी तो इस सम्बन्ध मे बातचीत चल रही है।

श्री फूलचन्द वर्मा मै जानना चाहता था कि किन किन यूनियनो के प्रतिनिधियो ने बात कही थी?

MR SPEAKER You did not ask a question, that was a suggestion Ask in the shape of a question, then, the question can be replied to If you give the suggestion, what can he say? You should read the rules for asking questions It should not give suggestions,

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्वेश्चन पूछा है। उस बैठक मे जो प्रतिनिधि थे उन्होने कहा था कि डाइरेक्ट मान्यता नही देनी चाहिए। मान्यता देने के लिए चुनाव कराना चाहिए। मै जानना चाहता हूँ कि किन किन लोगो ने ऐसा कहा था?

SHRI A P SHARMA Sir, I rise on a point of order,

MR SPEAKER I have not allowed it.

SHRI A P SHARMA I am only seeking a clarification from the hon Minister that if the answer given by him varies from the fact stated there . *(Interruption)*

MR. SPEAKER I have not allowed you.

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार गलत तरीके से मान्यता देने के

कारण नागदा में गोलीकांड हुआ, तीन आदमी मारे गये और अभी भी वहां पर औद्योगिक अशान्ति का खतरा बना हुआ है। सरकार मनमाने ढंग से रिकोगनीशन देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस मीटिंग में किन किन प्रतिनिधियों ने मान्यता देने के लिए चुनाव करवाने का सुझाव दिया।

श्री दामोदर पांडे : कोड आफ डिसिप्लिन में प्रोवीजन है कि ग्रीवेंसेज निपटाने के लिए वालेंटरी आर्गेनाइजेशन मंजूर की जाए . . .

अध्यक्ष महोदय : आप भी उसी तरफ चल पड़े।

SHRI DAMODAR PANDEY: It is in relation to this question. It mainly referring to public sector undertakings and that too concerning industrial relations. So, I want to know whether the public sector undertakings invariably do not accept the code of discipline and the method for eliminating the grievances of workmen by not accepting arbitration immediately even—after conciliation and mutual discussion.

SHRI BALGOVIND VERMA : What the hon. Member is suggesting is not correct because there is a definite procedure to look into the grievances. First of all, the Supervisor is there to look into it; then there is a committee to look into it and there is the Head of the Factory to look into it. There is also a joint works committee which goes into it.

MR. SPEAKER : Shri Indrajit Gupta.

SHRI DAMODAR PANDEY : My question was very specific, whether public sector undertakings are invariably refusing *(Interruption)*

MR. SPEAKER : I have called Shri Indrajit Gupta.

SHRI DAMODAR PANDEY : He has not replied to my question.

SHRI INDRAJIT GUPTA : In view of the fact, as the Minister has stated, that three months time has been given to the central trade union organisations to arrive at an agreed consensus on the question of collective bargaining, may I know whether the Government of India has considered taking steps to see that this effort to reach a consensus is not vitiated by the fact that in the meantime certain State Governments, particularly, the Governments of Maharashtra and Andhra Pradesh, have already brought forward Bills covering the same sphere and have taken certain positions and that the Government will see that those Bills are not given approval or consent until time is given to reach a consensus?

SHRI BALGOVIND VERMA : That is a suggestion.

Bokaro Steel Plant

*249. SHRI NIHAR LASKAR : Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the first stage of Bokaro Steel Plant will be completed by 1973; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAH NAWAZ KHAN) : (a) and (b). According to the present schedule construction of the entire first stage of the Bokaro Steel Plant is to be completed by March, 1973. All efforts are being made to adhere to this schedule.

SHRI NIHAR LASKAR : It is refreshing to hear the hon. Minister that they are trying to complete the entire first stage of the Bokaro Steel Plant by 1973. I would like to know what are the reasons for this optimism, whether they have overcome all the difficulties in regard to machinery and